

“भारत को ओआईसी से मिला निमंत्रण मुस्लिम दुनिया में संबंधों का विस्तार करने का एक सुनहरा अवसर है।”

पहली नजर में, भारत को इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की सभा को संबोधित करने का न्यौता मिलना बड़ी बात प्रतीत नहीं होती है। संशयवादियों द्वारा लंबे समय से तर्क दिया जाता रहा है कि ओआईसी को दुनिया के सबसे अप्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अप्रभावी टैग के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन और लीग ऑफ अरब नेशन्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने का गौरव प्राप्त है।

फिर भी, इस तथ्य पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि अबू धाबी में हो रही बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की भागीदारी, मुस्लिम दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के कम से कम समझ में आने वाले लेकिन सबसे सफल प्रयासों में से एक है, क्योंकि यह मध्य पूर्व के साथ भारत के संबंधों को फिर से संगठित करता है।

निश्चित रूप से, दुनिया भर के विश्लेषकों ने भी मोदी द्वारा स्पष्ट विरोधियों से भी दोस्ती का हाथ खुशी-खुशी बढ़ाते हुए देखा है, जिसमें सऊदी अरब और ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और कतर, मिस्र और तुर्की के साथ-साथ इजरायल और फिलिस्तीन भी शामिल हैं। इजरायल के साथ विशेष संबंध में मोदी की सफलता से भी पर्यवेक्षक काफी प्रभावित हुए हैं।

लेकिन मोदी की असली सफलता रूढ़िवादी अरब राजशाही, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत के प्रगाढ़ होते संबंध को माना जा सकता है। ये दोनों मुस्लिम देश लंबे समय से पाकिस्तान के सबसे करीबी अंतर्राष्ट्रीय भागीदार रहे हैं। इस्लामाबाद ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ मध्य पूर्व में अपने विशेष धार्मिक जुड़ाव को दर्शाते हुए इन देशों पर अपनी पकड़ को मजबूत बना रखा है।

हालाँकि, भारत का संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी हाउस के साथ राजनीतिक संबंध कई साल पीछे चला गया था, लेकिन श्री मोदी की सफल कूटनीति के कारण संबंधों ने एक विशेष रणनीतिक चरित्र हासिल करने में सफलता पाई है। इस संबंध की बढ़ती उत्पादक प्रकृति, मोदी और अरब जगत के प्रमुख नेताओं के बीच व्यक्तिगत राजनीतिक संबंध के एक अभूतपूर्व स्तर से आती है। यह धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद की धार को कुंद करने में भारत और अरब रूढ़िवादियों के बीच साझा हित में निहित है।

अतीत में, रूढ़िवादी अरब राजशाही राजनीतिक इस्लाम को प्रोत्साहित करने और दक्षिण एशिया में आतंक और धार्मिक चरमपंथ के लिए पाकिस्तानी सेना के समर्थन की निंदा करने के खतरों को अनदेखा करके खुश थे। आज, सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब राजतंत्रों की तुलना में किसी भी सरकार को धार्मिक अस्थिरता की ताकतों से ज्यादा खतरा नहीं है। इसने मुस्लिम दुनिया और मध्य पूर्व के साथ भारत के जुड़ाव के लिए एक नया ढांचा तैयार किया है।

समान रूप से महत्वपूर्ण भारत के साथ इस क्षेत्र की बढ़ती आर्थिक और ऊर्जा निर्भरता है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़े हाइड्रोकार्बन आयातकों और श्रम निर्यातकों में से एक के रूप में उभर रहा है। चूंकि इस क्षेत्र की भू-राजनीति एक अशांत अवधि में प्रवेश करती है, इसलिए एक सैन्य साझेदार के रूप में भी भारत को देखा जा रहा है। हम जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक है, जो निश्चित रूप से, स्वराज द्वारा ओआईसी को संबोधित करने के लिए आश्चर्यजनक आमंत्रण की व्याख्या करता है।

संयुक्त अरब अमीरात से निमंत्रण विशिष्ट है। ओआईसी में भारत के पर्यवेक्षक की स्थिति कमजोर नहीं प्रतीत होती है। अबू धाबी में मंत्रिस्तरीय बैठक में स्वराज की भागीदारी को सामूहिक रूप में इस्लामी दुनिया के निरंतर और दीर्घकालिक राजनीतिक जुड़ाव के लिए एक राजनयिक उद्घाटन के रूप में देखा जाना चाहिए।

दिल्ली को यह मानने की भूल नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान ओआईसी के कंधों का सहारा लेकर भारत को परेशान नहीं करेगा। इतने लंबे समय तक भारत को ओआईसी में अवरुद्ध करने के बाद, पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ओआईसी के साथ भारत के संबंधों को खराब करने के प्रयास को कम नहीं करने वाला है। पाकिस्तान भारत की कश्मीर नीति की आलोचना करने के लिए ओआईसी का उपयोग करने के किसी भी अवसर को नहीं छोड़ेगा।

हालाँकि, पिछले कुछ दिनों में मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि चीजें बदलने लगी हैं। दिल्ली के कुछ दोस्त ओआईसी (OIC) पर पाकिस्तान की कुछ भारत विरोधी ज्यादतियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब सदस्य देशों के बीच विवादों से निपटने की बात

आती है, तो एनएएम (NAM) की तरह ही OIC एक टूथलेस टाइगर (दांतों के बिना बाघ) है।

जब लीग के मामले में एनएएम और पैन-अरबवाद के मामले में तीसरा विश्ववाद उन्हें एक मजबूत ताकत में नहीं बांध सका, तो इस्लामिक पहचान कभी भी ओआईसी के लिए बहुत मजबूत नहीं होने वाला है। NAM और अरब लीग की तरह, OIC ने हमेशा अपने भीतर के कई राजनीतिक विरोधाभासों को दूर करने के लिए संघर्ष किया है। जबकि ओआईसी गैर-सदस्य देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में चिंता जताता है, यह कभी भी उन समस्याओं को नहीं उठा सकता है, जिनका मध्य पूर्व के देशों में शिया या सुन्नी अल्पसंख्यकों द्वारा सामना किया जा रहा है।

फिर सवाल यह उठता है कि ओआईसी में पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे संबंध के संदर्भ में नई दिल्ली इतना उतावला क्यों है? कहानी लगभग ढाई सदी पीछे चली जाती है। जैसा कि ब्रिटेन ने उपमहाद्वीप पर अपने क्षेत्रीय नियंत्रण को मजबूत किया था, लंदन के यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों को बार-बार मुस्लिम शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में भारत में ब्रिटिश संप्रभुता के खिलाफ जनता द्वारा विद्रोह के विचार से प्रलोभन दिया जाता था।

विभाजन और स्वतंत्रता के बाद समस्या समाप्त हो गई क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय मुसलमानों की तरफ से बोलने के अधिकार का दावा किया और इस्लामी दुनिया के साथ भारत के संबंध को गंभीर रूप से बाधित करने की मांग की।

सुषमा स्वराज को निमंत्रण, जो 50 साल बाद पाकिस्तान द्वारा ओआईसी को संस्थापक सत्र से भारत को हटाने के लिए मजबूर करने के बाद है, इस दुर्भाग्यपूर्ण विवाद को खत्म करने के लिए भारत के लिए उभरती संभावनाओं को चिह्नित करता है। एक गैर-वैचारिक और रुचि-आधारित संबंध भारत और मध्य पूर्व में रूढ़िवादी इस्लामिक देशों के लिए उपयुक्त लगता है।

भारत के पास खुश होने का अच्छा कारण है कि पाकिस्तान अब मध्य पूर्व के महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत के संबंधों को बिगाड़ने के लिए वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकता है। मध्य पूर्व में राजनीतिक मॉडरेशन और सामाजिक आधुनिकीकरण की उभरती ताकतों के लिए, भारत पाकिस्तान की तुलना में अधिक आकर्षक भागीदार है।

## GS World चीय...

### ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन (OIC)

#### चर्चा में क्यों?

- पहली बार भारत को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन (ओआईसी) की बैठक में 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के तौर पर आमंत्रित किया गया है।
- ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद् का 46वां सत्र 1 और 2 मार्च को अबू धाबी में होगा।
- पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच इस न्योते को माना जा रहा है भारत की कूटनीतिक जीत।
- सितंबर, 1969 में पाकिस्तान ने भारत को न्योते का विरोध किया था, जिस वजह से भारत को दिया गया निमंत्रण रद्द कर दिया गया।

#### क्या है?

- ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन (ओआईसी) मुस्लिम देशों का संगठन है। चार महादेशों में 57 देश इसके सदस्य हैं।
- 25 सितंबर, 1969 को मोरक्को की राजधानी रबात में मुस्लिम देशों का एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में इस संगठन की स्थापना का फैसला किया गया था।
- इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दाह में है।
- इसके मौजूदा महासचिव यूसुफ बिन अहमद अल उसैमीन हैं।
- इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स (आईसीएफएम) की 1970 में पहली मीटिंग हुई।
- इसमें 44 देश मुस्लिम प्रमुख देश हैं।

- इस संगठन की कही हुई बात को पूरे मुस्लिम समुदाय की संयुक्त राय का दर्जा दिया जाता है।

#### उद्देश्य:-

- इसका सबसे बड़ा उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी एकता के बंधन को मजबूत करना और उनके हितों की रक्षा करना है।
- यह संगठन सदस्य राष्ट्रों की अखंडता, उनकी स्वयत्तता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित रखने के लिए काम करता है।
- इस्लामी राष्ट्रों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सामान्य इस्लामी बाजार की स्थापना इसके अहम उद्देश्यों में से एक है।

#### इसमें शामिल देश?

- ओआईसी 1969 में बना ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में कुल 57 देश हैं।
- इन 57 देशों के नाम हैं- अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेनिन, बुनेई, दार-ए-सलाम, बुर्किना फासो, कैमरून, चाड, कोमोरोस, आईवरी कोस्ट, जिबूती, मिस्र, गैबॉन, गाम्बिया, गिनी, गिनी-बिसाऊ, गुयाना, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जार्डन, कजाखस्तान, कुवैत, किरगिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सेनेगल, सियरा लिओन, सोमालिया, सूडान, सूरीनाम, सीरिया, ताजिकिस्तान, टोगो, ट्यूनीशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, यमन।

संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

1. 'आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन सम्मेलन के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-
1. इस सम्मेलन में भारत पहली बार भागीदारी करेगा।
  2. इसके विदेश मंत्रियों की परिषद् के 46वें सत्र का आयोजन दोहा में किया जाएगा।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) 1 और 2 दोनों
  - (d) न तो 1 और न ही 2
1. Consider the following statements regarding the Organization of Islamic Cooperation (OIC) summit-
1. India will participate in this summit for the first time.
  2. It's 46th session of the Council of Foreign Ministers will be held in Doha.
- Which of the above statements is/are correct?
- (a) Only 1
  - (b) Only 2
  - (c) 1, 2 and 3
  - (d) Both 1 and 2

संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

- प्रश्न: भारत को ओआईसी से मिले निमंत्रण को देखते हुए इस्लामिक देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाने पर बल देना चाहिए? विश्लेषण कीजिए।
- Q. Viewing the invitation of the OIC to India, which type of strategy be emphasised for strengthening the relations among the Islamic countries? Analyze.

(250 Words)

नोट : 28 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।